पर्यावरण की शब्दावली का उपयोग कर अपने स्वार्थ को साध रही बड़ी कृषि कंपनियां

https://grain.org/e/6877

विश्व स्तर पर खाद्य व्यवस्था आज क्षत–विक्षत है, टूट रही है। यह विश्व स्तर पर हो रहे ग्रीन हाऊस गैस उत्सर्जन में से एक तिहाई के लिए जिम्मेदार है। विश्व में जैव विविधता उजड़ने का भी यह एक प्रमुख कारण है। दूसरी ओर विश्व में दस में से एक व्यक्ति को भूखे पेट सो जाना पड़ता है, जबकि करोड़ों लोग अस्वास्थ्यकर भोजन से जुड़ी मधुमेह, मोटापे, कैंसर जैसी बीमारियों से त्रस्त होते हैं। मौजूदा विश्व खाद्य व्यवस्था नए रोगों व महामारियों के लिए भी एक मुख्य कारक है।

सामाजिक आंदोलन व समुदाय कई दशकों से इस मौजूदा हानिकारक खाद्य व्यवस्था के विकल्प तैयार करने के लिए प्रयासरत हैं। इनमें से अनेक आंदोलन अपनी पहचान खाद्य संप्रभुता के विश्व स्तर के आंदोलन के एक भागीदार के रूप में करते हैं जिसमें खाद्य उत्पादन स्थानीय समुदायों की जरूरतों व संस्कृति पर आधारित हैं व स्थानीय पर्यावरण की रक्षा पर आधारित हैं व दूर–दराज की कंपनियों के मुनाफे पर आधारित नहीं है। जमीनी स्तर के कृषि प्रयास देशीय व लघु कृषक समुदायों के उस ज्ञान पर आधारित हैं जो अनेक पीढ़ियों के अनुभवों से एकत्र हुआ है व जिससे आज हमें जलवायु बदलाव के संकट से जूझने के उपाय भी मिलते हैं। अनेक आंदोलन इन प्रयासों व प्रवृत्तियों को 'एग्रो इकालाजी' या 'कृषि पारिस्थितिकि' का नाम देते हैं यानि ऐसी कृषि व्यवस्था जो सही अर्थों में पर्यावरण की सही समझ व उसकी रक्षा पर आधारित हों।

कृषि को बहुत बड़े बिजनेस की तरह अपनाने वाली बड़ी कंपनियों के स्वार्थों के लिए खाद्य संप्रभुता व 'कृषि पारिस्थितिकि' की सोच से बहुत कठिनाई उत्पन्न होती है। खाद्य संप्रभुता व 'कृषि पारिस्थितिकि' की व्यवस्था में इन बड़ी कंपनियों के मुनाफे के लिए कोई स्थान नहीं है। इनमें उन जेनेटिक रूप से संवर्धित फसलों या जीवन रूपों (जीएमओ), संकरित बीजों व कृषि रसायनों का उपयोग नहीं होता है जिन्हें कृषि बिजनेस कंपनियां बेचती हैं। उनसे वैसी एकरूपता वाली फसलों की आपूर्ति भी नहीं होती है जो कृषि बिजनेस कंपनियों की प्रोसेसिंग फेक्ट्रियों या फैक्ट्री जैसे फार्मों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इस स्थिति में जब सामाजिक आंदोलन आगे बढ़ रहे हैं व खाद्य संप्रभुता और 'कृषि पारिस्थितिकि' को जलवायु बदलाव के संकट के एक महत्त्वपूर्ण समाधान के रूप में बढ़ती मान्यता मिल रही है तो उनके महत्त्व व प्रभाव को कम करने या क्षतिग्रस्त करने के लिए बड़ी कृषि व खाद्य बिजनेस कंपनियों ने अपने प्रयास तेज कर दिएं हैं।

इन कुप्रयासों में कृषि बिजनेस कंपनियों का एक मुख्य उपाय है ग्रीनवाशिंग यानि पर्यावरण रक्षा के बारे में ऐसी भ्रामक स्थिति उत्पन्न करना जिससे उनका उल्लू सीधा हो सके, उनके स्वार्थ सध सकें। यह इन कंपनियों का अपना व्यवसाय व बिक्री बढ़ाने तथा विज्ञापन का ऐसा उपाय है जिससे यह कंपनियां पर्यावरण समस्याओं को स्वीकार तो करती हैं पर साथ में ऐसी भ्रामक व असत्य जानकारी प्रसारित करती हैं जिससे यह प्रतीत हो कि उनके कार्यों, व्यवसाय व उत्पादों से इन पर्यावरण समस्याओं का समाधान हो रहा है। यदि आप इन बड़ी कृषि व खाद्य कंपनियों की वेबसाईट को या इनकी वार्षिक रिपोर्टों को देखें तो आपको पहली नजर में ऐसा भ्रम हो सकता है कि इनका उद्देश्य धरती को बचाना व जलवायु बदलाव की समस्या का समाधान है। इनका दावा है कि वन विनाश को रोकेंगे, जैव विविधता को बचाएंगे, जलवायु बदलाव के संकट का समाधान करेंगे, भूख की समस्या दूर करेंगे। वे मानव अधिकारों व देशीय समुदायों के भूमि–अधिकारों की रक्षा का दावा भी करती हैं। इन दावों के बावजूद वे उन्हीं उत्पादों को बेचते रहते हैं व वस्तु उत्पादन तथा उपभोग के ऐसे ही मॉडल का प्रसार करते रहते हैं जो हमारी धरती को बर्बाद कर रहे हैं और अपनी जैव–विविधता व भूमि पर लोगों की हकदारी व नियंत्रण को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। जिस तरह शेल (Shell) व एक्सान (Exxon) जैसी कंपनियों ने 'ग्रीनवाशिंग' का उपयोग कर किसी न किसी तरह पर्यावरण रक्षा के प्रति अपनी गंभीरता सिद्ध करने का प्रयास किया है, उसी तरह खाद्य व कृषि बिजनेस कंपनियों ने इसका उपयोग लोगों को भ्रमित करने या ऐसी कार्यवाही से बचने के लिए किया है जिसका उनके मुनाफों पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।

निम्न पृष्ठों में, हमने ग्रीनवाशिंग के कुछ हथकंडों को स्पष्ट करने का प्रयास किया है जो झूठे समाधान प्रस्तुत करते हैं व जलवायु बदलाव के समाधानों से ध्यान हटाते हैं।

'शूद्ध शून्य या नेट जीरो' (Net Zero) कार्बन उत्सर्जन

संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार 'नेट जीरो' का अर्थ है "ग्रीनहाऊस गैसों के उत्सर्जन को जितना संभव हो शून्य के पास ले जाना, व जो भी शेष उत्सर्जन हो उसको वायुमंडल में सोखने की व्यवस्था करना।" सरल शब्दों में कमी + हटाना = शून्य ग्रीनहाऊस गैस उत्सर्जन। वर्ष 2015 में विश्व की सरकारों ने वर्ष 2050 तक 'नेट जीरो' कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने पर सहमति बनाई और उसके बाद तो 'नेट जीरो' के लिए प्रतिबद्धता की एक बाढ़ सी आ गई – सरकारों द्वारा व स्वैच्छिकता से विभिन्न कारपोरेशनों (निगमों या कंपनियों) द्वारा भी।

विभिन्न कंपनियों की 'नेट जीरो' के लिए प्रतिबद्धता में समस्या यह है कि वे कहीं भी वास्तविक शून्य के आसपास नहीं हैं। कंपनियां 'नेट जीरो' के हिसाब–किताब का अपने ढंग से उपयोग महज अपने उत्सर्जन में वास्तविक महत्त्वपूर्ण कमी लाने से बचने के लिए कर रही हैं। यह कंपनियां प्रायः यह दावा कर रही हैं कि उन्हें अपने उत्सर्जन को कम करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि वे इसके बराबर की कमी ऐसी परियोजनाओं से ला सकती हैं जो वृक्ष लगाकर, वन बचाकर या जियो–इंजीनियरिंग (Geo-Engineering) से ग्रीनहाऊस गैसों को हटाती हैं। यह एक भ्रम जाल है, धोखा है।

ऐसी ही एक कंपनी नेस्ले (Nestle) का उदाहरण लेते हैं। कंपनी का दावा है कि अधिक उत्सर्जन करने वाले अपने उत्पादों जैसे डेयरी व मांसाहारी उत्पादों में वर्ष 2020–2030 में दो–तिहाई वृद्धि के बावजूद वह 'नेट जीरो' प्राप्त कर सकेगी क्योंकि वह पेड़ लगाएगी व वन रक्षा भी करेगी। पर हिसाब लगाएं तो इसके लिए उसे 40 लाख हैक्टेयर भूमि की आवश्यकता पेड़ लगाने या संरक्षण के लिए होगी, जो कि उसके मूल देश स्विटजरलैंड के क्षेत्रफल से भी अधिक है। यह आंकड़े आपस में मेल नहीं रखते हैं, विशेषकर यह ध्यान में रखते हुए कि नेस्ले के साथ सैंकड़ों अन्य कंपनियां भी अपने उत्सर्जन बढ़ाते हुए या कायम रखते हुए पेड़ों व संरक्षण के माध्यम से उत्सर्जन कम करने का दावा कर रही है।

वर्ष 2050 तक वास्तविकता में 'नेट जीरो' प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि सभी ग्रीनहाऊस गैस उत्सर्जनों को रोक दिया जाए खासकर जो अत्यंत आवश्यक ग्रीनहाऊस गैस उत्सर्जनों हैं। नेस्ले व ऐसी अनेक कृषि व खाद्य बिजनेस कंपनियों

के उत्सर्जन इस 'अत्यंत आवश्यक' तरह के नहीं हैं। ऐसे अनेक कम उत्सर्जन खाद्य व्यवस्था विकल्प मौजूद हैं जो उत्सर्जन के बिना विश्व के लिए भली–भांति खाद्य व पोषण की व्यवस्था कर सकते हैं।

इस विषय की अधिक जानकारी के लिए इसे पढ़े (अंग्रेजी में):

- Corporate Accountability, Global Forest Coalition, Friends of the Earth International, 2021, The Big Con: How Big Polluters are advancing a "net zero" climate agenda to delay, deceive, and deny https://www.corporateaccountability.org/resources/the-big-con-net-zero/
- Friends of the Earth International, 2021, Chasing Carbon Unicorns: The deception of carbon markets and "net zero" https://www.foei.org/publication/chasing-unicorns-carbon-markets-net-zero/
- GRAIN, 2021, Corporate greenwashing: "net zero" and "nature-based solutions" are a deadly fraud https://grain.org/e/6634

कार्बन ऑफसेट (Carbon Offsets)

कार्बन ऑफसेट एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से कोई सरकार या कंपनी अपने उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति के लिए उन परियोजनाओं द्वारा सृजित कार्बन क्रेडिट खरीदती है जो ग्रीनहाऊस गैसों (जीएचजी) से बचाते हैं, इन्हें कम करते हैं या हटाते हैं। कार्बन के बाजार में एक तरह से प्रदूषण की अनुमति का व्यापार होता है।

यू.के. (United Kingdom), चीन, न्यूजीलैंड या कोरिया गणराज्य जैसे कुछ देशों में ऐसे कानून या नियम बने हैं जो कंपनियों को क्रमबद्ध अपने ग्रीनहाऊस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए बाध्य करते हैं, इसके लिए उत्सर्जन की अधिकतम सीमा निर्धारण करते हैं पर इसके ऊपर के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति के लिए अन्य कंपनियों से कार्बन क्रेडिट या अधिकार खरीदने–बेचने की अनुमति भी देते हैं। यह अनिवार्य कार्बन बाजार है जिन्हें उत्सर्जन व्यापार व्यवस्था (एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम या ईटीएस) भी कहा जाता है। किन्तु अधिकांश कार्बन क्षतिपूर्ति परियोजनाएं स्वैच्छिक बाजार में कार्बन बेचती हैं जहां मानदंड लचीले होते हैं व कार्बन क्रेडिट मूल्य दस गुणा तक कम हो सकते हैं। हालांकि यह कार्बन क्रेडिट अभी तक किसी देश की सरकारी तौर पर मान्यता प्राप्त उत्सर्जन कमी में उपयोग नहीं हो सकते हैं पर इनके असर से अनिवार्य बाजार में भी कार्बन क्रेडिट के मूल्य में कमी आ जाती है और इनके माध्यम से कंपनियों को उत्सर्जन की क्षति पूर्ति के दावों के प्रचार का अवसर भी मिल जाता है। स्वैच्छिक बाजारों में मांग बढ़ रही है क्योंकि कंपनियों की 'नेट जीरो' की तथाकथित प्रतिबद्धताएं बहुत हद तक ऐसी क्षतिपूर्ति पर आधारित होती हैं व यह स्थिति इस तथ्य से जुड़ी है कि यह कंपनियां उत्सर्जन में प्रत्यक्ष कमी से बचती हैं। वर्ष 2021 में वनों और भूमि से जुड़ी कथित क्षतिपूर्ति में 159 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, व पूरे कार्बन क्रेडिट बाजार में इसका एक तिहाई का हिस्सा रहा।

ऐसी अनेकोनेक कंपनियों, परामर्शदाताओं व एनजीओ का एक बड़ा व्यवसाय पनप गया है जो बड़े पैमाने के वृक्ष–प्लांटेशन या कृषि कार्यक्रम के आधार पर मिट्टी में कार्बन फिर व्यवस्थित करने का दावा करते हैं व इस माध्यम से उत्सर्जन क्षतिपूर्ति की व्यवस्था का दावा करते हैं। इन स्कीमों के नियमन के लिए सुव्यवस्थित निश्चित मानदंड नहीं है व क्षतिपूर्ति या ऑफसेट का बिजनेस धोखे व अनुचित हिसाब–किताब से भरा हुआ है। यह परियोजनाएं प्रायः विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में पनप रही होती है जहां परियोजनाओं का खर्च व कार्बन मूल्य कम होते हैं व स्थानीय लोगों की जल, जंगल, जमीन पर हकदारी भी इनसे कम हो सकती है। इसके बावजूद इन क्षतिपूर्ति परियोजनाओं में भागेदारी करने वाले समुदायों को प्राप्त होने वाले कार्बन क्रेडिट का अपेक्षाकृत बहुत कम भाग ही प्राप्त होता है (यदि कुछ मुआवजा प्राप्त होता भी है तो) इन देशों से उत्सर्जन क्षतिपूर्ति के नाम पर जो भूमि हथियाई जा रही है उसे कार्बन उपनिवेशवाद (Carbon Colonialism) का नाम दिया गया है।

इस विषय की अधिक जानकारी के लिए इसे पढ़े (अंग्रेजी में):

- Camila Moreno, Daniel Speich Chassé and Lili Fuhr, 2016, Carbon metrics. Global abstractions and ecological epistemicide https://www.boell.de/sites/default/files/20161108_carbon_metrics_2._auflage.pdf
- Friends of the Earth International, 2022, Fossil futures built on a house of cards https://www.foei.org/publication/fossil-futures-built-on-a-house-of-cards/
- Indigenous Environmental Network, ETC Group, et. al., 2021, Hoodwinked in the Hothouse https://climatefalsesolutions.org/wp-content/uploads/HOODWINKED_ThirdEdition_On-Screen_version.pdf

प्रकृति आधारित समाधान (Nature-Based Solutions)

प्रकृति आधारित समाधान या नेचर बेस्ड सोल्यूशन (एनबीएस) शब्दों का उपयोग पहले कुछ बड़ी संरक्षण एनजीओ ने अपने लिए वित्तीय संसाधन एकत्र करने के लिए किया व संरक्षित वनों के विविध लाभों को रेखांकित किया। इन दिनों इस शब्दावली का अधिक उपयोग कंपनियों व सरकारों द्वारा कार्बन क्षतिपूर्ति के माध्यम से नेट जीरों का लक्ष्य प्राप्त करने के संदर्भ में किया जा रहा है। विश्व बैंक ने ऐसी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता दी है जो किसी पर्यावरण सिस्टम की सेवाओं की मौद्रिक कीमत तय करती है व जलवायु बदलाव तथा जैव विविधता संरक्षण के बाजार–आधारित समाधान तैयार करती है। इस विमर्श में कहा जा रहा है कि संरक्षित वनों, दलदलों, समुद्रों, कृषि भूमि व वृक्ष प्लांटेशन के रूप में प्रकृति का दोहन वायुमंडल में मौजूद ग्रीनहाऊस गैस उत्सर्जन के 37 प्रतिशत हिस्से को हटाने के लिए किया जा सकता है। यह भी कहा जा रहा है कि इस हटाने की संख्यात्मक नाप कर उन्हें प्रदूषण करने वाली कंपनियों को अपने जारी रहने वाले प्रदूषण की क्षतिपूर्ति के रूप में बेचा जा सकता है। एनबीएस को संयुक्त राष्ट्र संघ की पर्यावरण असेंबली द्वारा बहुत व्यापक स्तर पर परिभाषित करने के बाद इसके अन्तर्गत बहुत सी गतिविधियों व कार्यवाहियों आ जाती है।

इन 'प्रकृति आधारित समाधानों' के कारण बहुत सी भूमि की इस तरह घेराबंदी की जा रही है कि यह स्थानीय समुदायों की पंहुच से बाहर हो जाए। उदाहरण के लिए फ्रांस की विशालकाय तेल–पेट्रोल कंपनी टोटल (Total), कांगो (Congo) गणराज्य में 40,000 हैक्टेयर क्षेत्र में ऐसा फार्म बना रही है जहां वनों का कभी विनाश नहीं करने वाले Pygmy आदिवासी बहुत पहले से रहते आए हैं ताकि वह बहुत प्रदूषण करने वाले नए तेल संसाधन खोजने की परियोजना की क्षतिपूर्ति कर सके। यूरोप की अन्य प्रमुख ऊर्जा कंपनियां एनी (Eni) व शैल (Shell) को हर वर्ष 80 लाख हैक्टेयर भूमि की घेराबंदी कर उसपर पेड़ लगाने होंगे ताकि उनके वर्ष 2050 तक के जीवाश्म ईंधन (फॉसिल फ्यूल) के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति हो सके। अन्य 'प्रकृति आधारित समाधानों' के अन्तर्गत बड़ी कंपनियां बहुत से कृषि क्षेत्र में कार्बन फार्मिंग कार्यक्रमों के अंतर्गत कार्बन को धरती में सोखने का कार्य कर रही है, जिसे कार्बन सिंक (Carbon Sink) कहते है।

इस संदर्भ में 'प्रकृति आधारित समाधानों' को ठीक ही 'प्रकृति आधारित छीनाछपटी' कहा जा रहा है क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत सी भूमि और वनों से, विशेषकर विकासशील देशों में, जनसाधारण वंचित किए जा रहे हैं। प्रकृति आधारित समाधान एक बहुत बड़ा धोखा है। यह इस मान्यता पर आधारित है कि जितने भी जीवाश्म ईंधन उपयोग हों उनके उत्सर्जन को उतनी ही मात्रा में कार्बन के रूप में वनों, मिट्टी व समुद्रों में सोखा जा सके। इस मान्यता को जलवायु वैज्ञानिक व्यापक स्तर पर अस्वीकार कर चुके हैं।

इस विषय की अधिक जानकारी के लिए इसे पढ़े (अंग्रेजी में):

- Alianza Biodiversidad, AFSA, ETC group, Focus on the Global South, GRAIN, FoEI, ICA, IEN, and WRM, 2022, Press conference on 15 March: No to Nature Based Solutions! https://grain.org/e/6816
- GRAIN, 2021, Corporate greenwashing: "net zero" and "nature-based solutions" are a deadly fraud https://grain.org/e/6634
- World Rainforest Movement, 2021, Nature-based Solutions: Concealing a massive land robbery https://www.wrm.org.uy/bulletins/issue-255

शून्य वन–विनाश (Zero Deforestation)

वन–विनाश के कारण जलवायु बदलाव व जैव विविधता क्षति को बहुत बढ़ावा मिलता है। इस ओर अब अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। इस स्थिति में विश्व की बड़ी खाद्य कंपनियों ने वर्ष 2010 में कहा कि वे अपनी आपूर्ति श्रृंखला में वर्ष 2020 तक इस तरह के बदलाव ले आएंगी जिससे उनके कारण वन–विनाश की संभावना पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। उन्हांने इसी तरह की प्रतिबद्धता वर्ष 2014 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु महासम्मेलन में व फिर वर्ष 2021 के जलवायु महासम्मेलन में दोहराई। इसके लिए एक–तिहाई धन निजी क्षेत्र के निवेशकों व परिसंपत्ति प्रबंधकों से प्राप्त होना था। पर इस तरह के स्वैच्छिक घोषित वायदों से वन–विनाश की दर में कोई कमी नहीं आई है। आज भी 27 फुटबाल मैदानों जितना बड़ा वन क्षेत्र प्रति मिनट नष्ट हो रहा है व ब्राजील में अमेजन का वन विनाश वर्ष 2022 के पहले छः महीनों में अपने चरम पर पहुंच गया।

वन–विनाश का सबसे बड़ा कारण है वैश्विक स्तर पर हो रहे कुछ कृषि व खाद्य उत्पादों का उत्पादन जैसे सोयाबीन, पॉम तेल व गोमांस। जब तक ऐसे उत्पादों की मांग बढ़ती रहेंगी, वन–विनाश भी बढ़ता रहेगा। पर अनेक खाद्य व कृषि कंपनियां न तो इनका उत्पादन घटा रही हैं व न ही इस कारण हो रहे वन–विनाश की जिम्मेदारी को स्वीकार कर रही हैं। अतः वे क्लाईमेट स्मार्ट कृषि व 'सर्टिफिकेशन स्कीमों' की आड़ में अपने उत्पादों का 'ग्रीनवाशिंग' कर रही हैं न की वन–विनाश रोक रही है, यानि महज जुमलों से अपने द्वारा किए गए पर्यावरण विनाश से ध्यान हटा रही हैं।

इन कंपनियों की जीरो 'वन–विनाश' योजनाएं अनेक विसंगतियों व कार्यान्वयन स्तर की समस्याओं से भरी हुई हैं। वे कुछ विशेष तरह के उत्पादों व वनों तक सीमित हैं व पहले हुए वन–विनाश या अप्रत्यक्ष वन–विनाश की उपेक्षा करती हैं। जिस भूमि को एक दशक से पहले ही समुदायों से छीन कर इस पर वन–विनाश किया गया कारगिल (Cargill) कंपनी उससे मक्का खरीदते समय अपने को वन–विनाश के दोषारोपण से मुक्त मानती है क्योंकि यह तो कुछ वर्ष पहले का अन्याय है। यूनिलीवर (Unilever) कंपनी जब ऐसी प्लांटेशन से पॉम तेल खरीदती हैं जहां सामुदायिक वनों को नष्ट किया गया तो यह कह कर पल्ला झाड़ लिया जाता है कि वे वन 'उच्च संरक्षण मूल्य' के नहीं थे। ब्राजील के चरागाहों को नष्ट करने से ही पशु आधारित व्यवसाय के लिए अमेजन वन पर बोझ बढ़ा, पर बड़ी कंपनियां (जैसे Bunge) इस नष्ट हुए चरागाह से सोयाबीन खरीदते वक्त अपने को वन–विनाश के दोष से मुक्त रखने का पूरा प्रयास करती है।

इतना ही नहीं, जब कंपनियों को अपनी ही सर्टिफिकेशन स्कीमों का उल्लंघन करते देखा जाता है, जैसाकि प्रायः होता रहता है, तो इसके लिए कोई दंड भी नहीं है क्योंकि यह स्कीमें बाध्यकारी न होकर स्वैच्छिक मानी गई है। नेस्ले (Nestle) व ड्युश बैंक (Deutsche Bank) ने वर्ष 2014 की शून्य वन विनाश की प्रतिबद्धता पर हस्ताक्षर तो किए, पर उन्होंने ऐसी कंपनियों से खरीद व वित्त के संबंध बनाए रखे जो अमेजन के अवैध वन विनाश के क्षेत्र में गोमांस उत्पादन व पशु आधारित व्यवसाय करती है। जब इस तरह के आरोप लगते हैं तो यह कंपनियां उनकी अवहेलना यह कह कर करती हैं कि वे ऐसी नई तकनीको (जैसे ब्लॉकचैन) को आजमा रही है जो अभी आरंभिक स्थिति में है। पर फिलहाल तो 'शून्य वन विनाश' का ठप्पा लगाकर वे ऐसे खाद्यों व उत्पादों को बढ़ावा दे रही हैं जो वास्तव में वन–विनाश से जुड़े हैं व इस तरह यह कंपनियां वन–विनाश को भी बढ़ावा दे रही हैं।

इस विषय की अधिक जानकारी के लिए इसे पढ़े (अंग्रेजी में):

- ENCO, 2021, Invisible hands? European corporations and the deforestation of the Amazon and Cerrado biomes https://corpwatchers.eu/en/investigations/european-multinationals-and-authoritarian-regimes/invisible-hands-european-corporations-and-the-deforestation-of-the-amazon-and?lang=en
- GRAIN, 2021, Agribusiness and big finance's dirty alliance is anything but "green" https://grain.org/e/6720
- Greenpeace, 2021, Destruction: Certified https://www.greenpeace.org/static/planet4-international-stateless/2021/04/b1e486be-greenpeace-international-report-destruction-certified_finaloptimised.pdf
- WRM, 2022, 15 Years of REDD: A Mechanism Rotten at the Core https://www.wrm.org.uy/publications/15-years-of-redd

कृषि 4.0 (Agriculture 4.0)

'चौथी औद्योगिक क्रान्ति' या उद्योग 4.0 एक ऐसी सोच का सिद्धांत है जिसे विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum) के अभियानों ने कृत्रिम बौद्धिकता (artificial intelligence), जीन एडिटिंग व आधुनिक रोबोटिक (advanced robotics) विज्ञान की तकनीकों के संदर्भ में उपयोग किया है।

अभी तक तो इसके अधिकांश खाद्य उत्पादकों पर होने वाले असर में कुछ अदभुद नजर नहीं आता है। उच्च तकनीक की मशीनों जैसे ड्रोन, ड्राईवर विहीन ट्रैक्टरों व रोबोट से कुछ बहुत बड़े फार्मों को अपना आकार व उत्पादन बढ़ाने में मदद मिल सकती है पर यह तकनीकें छोटे किसानों के लिए बहुत महंगी है व इन्हें तैयार करने में छोटे किसानों की जरूरतों व हितों को ध्यान में भी नहीं रखा गया है। नई तकनीकों से ग्रामीण रोजगार भी उजड़ते हैं क्योंकि उनसे कई कृषि श्रमिक विस्थापित हो सकते हैं। 'कृषि 4.0' एक ऐसे डिजिटल ढांचे से भी जुड़ी है, जो अपनी आपूर्ति श्रृंखला सहित बहुत हानिकारक पर्यावरणीय असर के लिए जिम्मेदार है, विशेषकर विकासशील देशों में।

कृषि बिजनेस व डिजिटल कंपनियों जैसे माईक्रोसाफ्ट के डिजिटल कृषि प्लेटफार्मों से छोटे किसानों को बहुत कम लाभ मिल पाता है। छोटे किसान प्रायः उन क्षेत्रों में होते हैं जहां विस्तार सेवाएं नहीं होती हैं व डिजिटल प्लेटफार्मों की महंगी डेटा एकत्र करने वाली तकनीकें उनके लिए बहुत महंगी व प्रायः पंहुच से बाहर सिद्ध होती हैं। यह प्रोग्राम प्रायः बड़े पैमाने के मोनोकल्चर (एअल फसल चक्र) व फैक्ट्री फार्मों के लिए डिजाईन किए जाते हैं। अच्छी गुणवत्ता के डाटा के बिना डिजिटल प्लेटफार्म छोटे किसानों को उच्च स्तरीय जानकारी व सलाह नहीं दे सकते हैं, विशषकर उन किसानों को जो 'एग्रोइकालाजी' के आधार पर कार्य करते हैं, जो देशीय पशुओं व स्थानीय बीजों का उपयोग करते हैं व विविधता भरी फसलों को उगाते हैं। पर बड़ी कंपनियों की डिजिटल खेती के प्रसार की अपनी वजह है। डिजिटल प्लेटफार्म, विशेषकर जब उन्हें (सेल फोन के माध्यम से) डिजिटल धन व्यवस्था से जोड़ दिया जाता है, इसमें सहायक होते हैं कि लाखों छोटे किसानों को केन्द्रकृत डिजिटल जाल में जोड़ दिया जाए ताकि वे बड़ी कंपनियों के उत्पादों (जीएम बीज, कीटनाशक, खरपतवार नाशक मशीनों आदि) को खरीदने के लिए प्रोत्साहित हों, व प्रायः इसके साथ ग्रामीण बीमा व वित्तीय सेवाओं को लेने की शर्त भी जोड़ दी जाती है। इस तरह कृषि की यह तथाकथित क्रान्ति छोटे किसानों के बड़ी बिजनेस कंपनियों द्वारा दोहन का मार्ग प्रशस्त करती है।

'कृषि 4.0' की शब्दावली लोगों का ध्यान नई तकनीकों से जुड़े महत्त्वपूर्ण राजनीतिक संघर्ष से हटाती है। डिजिटल तकनीकों व प्लेटफार्म को ऐसा रूप भी दिया जा सकता है कि वह वास्तव में छोटे खाद्य उत्पादकों व श्रमिकों के लिए मददगार हों, व खाद्य संप्रभुता में मददगार हों तथा ऐसे अनेक प्रयास हो भी रहे हैं। पर आज स्थिति यह है कि कृषि क्षेत्र में अधिकांश नई तकनीकों पर व डिजिटल प्लेटफार्मों पर उन बड़ी कृषि बिजनेस कंपनियों का नियंत्रण है जो श्रमिकों और किसानों का शोषण कर मुनाफा कमाती हैं, व उनकी कृषि सम्बंधित डाटा की चोरी करती हैं। जरूरत इस बात की है कि खाद्य संप्रभुता के आंदोलन डिजिटल न्याय के आंदोलन के साथ भागेदारी स्थापित करें व वे मिलकर कृषि व खाद्य व्यवस्था पर बढ़ते कारपोरेट नियंत्रण का सामना करें।

इस विषय की अधिक जानकारी के लिए इसे पढ़े (अंग्रेजी में):

- ETC Group 2018, Blocking the chain. Industrial food chain concentration. Big data platforms and food sovereignty solutions https://www.etcgroup.org/content/blocking-chain
- GRAIN, 2021, Digital control: how Big Tech moves into food and farming (and what it means) https://grain.org/e/6595
- GRAIN, 2022, The digitalisation of land: more data, less land https://grain.org/e/6832

क्लाईमेट स्मार्ट कृषि (Climate Smart Agriculture)

लगभग एक दशक पहले जब विश्व स्तर पर 'एग्रो इकालाजी' (कृषि पारिस्थितिकि) या पर्यावरण रक्षा से सही अर्थों में जुड़ी कृषि के लिए वास्तव में समर्थन बनने लगा तो बड़ी कृषि बिजनेस कंपनियों ने इसके विरोध में 'क्लाईमेट स्मार्ट कृषि' की आकर्षक शब्दावली की आड़ में अपने स्वार्थ की सोच को नए सिरे से जमाने की कोशिश की। विश्व की सबसे बड़ी रासायनिक खाद कंपनियों ने इसके लिए बहुत बड़ा प्रचार अभियान कर इसे मुख्य धारा में पंहुचाया व विश्व स्तर पर बड़ी कंपनियों, सरकारों व अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों जैसे विश्व बैंक व खाद्य व कृषि संगठन (एफएओ) का गठजोड़ इसके पक्ष में जुटाया।

जहां 'एग्रोइकालाजी' हमें औद्योगिक कृषि या फैक्ट्री खेत के मॉडल से हटने में मदद करती है, वहां 'क्लाईमेट स्मार्ट कृषि' औद्योगिक कृषि से दूर हटने के बड़े व वास्तविक बदलाव व इसकी हानियों की समझ से ध्यान हटा कर छोटे–मोटे गीनहाऊस गैस उत्सर्जन कम करने के उपायों तक सीमित रखती है। इन कंपनियों का प्रचार कहता है कि रासायनिक खाद का उपयोग भी 'क्लाईमेट स्मार्ट' है (यानि जलवायु बदलाव का संकट कम करने में मददगार है) क्योंकि इससे उत्पादकता बढ़ती है व कृषि को वन भूमि पर बढ़ाने की जरूरत कम होती है। इनके आनुसार, खतरनाक खरपतवारनाशकों का उपयोग 'क्लाईमेट स्मार्ट' है क्योंकि जुताई की जरूरत कम होगी व इससे कम कार्बन वायुमंडल में जाएगा। दूसरी ओर चरागाहों पर 'सोयाबीन प्लांटेशन' लगाना भी 'क्लाईमेट स्मार्ट' है क्योंकि वे वायुमंडल से नाईट्रोजन व्यवस्थित करते हैं व इस तरह नाईट्रोजन रासायनिक खाद की जरूरत कम करते हैं।

इस तरह किसी न किसी तिकड़म से औद्योगिक कृषि की विभिन्न प्रवृत्तियों पर 'क्लाईमेट स्मार्ट' का ठप्पा लगा कर उसे सही सिद्ध किया गया है, व इस तरह रासायनिक कीटनाशकों व खाद, ड्रिप सिंचाई पद्धति, बड़े पैमाने के मोनोकल्चर या एक ही फसल व किस्म को बड़े क्षेत्र में उगाने की प्रवृत्ति, जी.एम. या जेनेटिक दृष्टि से संवर्धित फसलों व खेत को फैक्ट्री जैसे उपयोग करने की प्रवृत्तियों को 'क्लाईमेट स्मार्ट कृषि' के नाम पर सही ठहराया जाता है जो कि बहुत अनुचित है। इस तरह जलवायु संकट के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार 'औद्योगिक कृषि' के मॉडल को ग्रीनवाश कर इसे उचित सिद्ध किया जाता है, जबकि जरूरत तो इस 'औद्योगिक कृषि' के मॉडल को हटाने की व इसके स्थान पर एग्रो–इकालाजी (कृषि पारिस्थितिकि) को लाने की है।

इस विषय की अधिक जानकारी के लिए इसे पढ़े (अंग्रेजी में):

- CIDSE, 2014, 'Climate-Smart Agriculture': the Emperor's new clothes? https://www.cidse.org/wp-content/uploads/2015/09/821_CIDSE_Climate-Smart_Agriculture_EN_1.pdf
- ETC Group, Heinrich Böll Stiftung, 2015, Outsmarting Nature: Synthetic Biology and Climate Smart Agriculture https://www.boell.de/sites/default/files/2015-11-outsmarting-nature-synthetic-biology.pdf
- GRAIN, 2015, The Exxons of agriculture https://grain.org/e/5270

पुनर्योजी या रीजेनरेटिव कृषि (Regenerative Agriculture)

यह भी एक ऐसी शब्दावली है जिसका उपयोग अलग–अलग लोग अपने मनमाने ढंग से करते हैं। जहां जैविक (आर्गेनिक) खेती व एग्रो इकालाजी व्यापक सहमति के सिद्धांतो पर आधारित है व इनमें रासायनिक खाद, कीटनाशक व जीएमओ का उपयोग नहीं होता हैं, वहां रीजेनरेटिव कृषि में ऐसी कोई मनाही नहीं है व इसका अर्थ ऐसी किसी भी कृषि से लगा दिया जाता है जो मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने का दावा करती है व मिट्टी में कार्बन के पुनर्निमाण में सहायक होती। यही वजह है के ये शब्दावली पिछले कुछ सालों में बड़ी खाद्य व कृषि कंपनियां में काफी लोकप्रिय हो गई है।

बड़ी खाद्य कंपनियां जैसे ADM, Cargill, Danone और Nestle अपनी जलवायु पहलों के हिस्से के रूप में रीजेनरेटिव कृषि कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं। अन्य कॉर्पोरेट नेतृत्व वाले संस्थान जैसे कि खाद्य और भूमि उपयोग गठबंधन (Food and Land Use Coalition) और विश्व

आर्थिक मंच (World Economic Forum) समान कार्यक्रमों का समर्थन करते हैं। वे किसानों को अपनी कृषि पद्धतियों को उन तरीकों से बदलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जो रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने और मिट्टी में कार्बन वापस बनाने के लिए है। पर बड़ी कंपनियां इन कार्यक्रमों में अपना अधिक पैसा नहीं लगा रही हैं। दनानो (Danone) ने इसके लिए एक वर्ष में इतना ही पैसा दिया है जो उसकी एक दिन की विक्री के बराबर हे। नेस्ले (Nestle) ने इसके लिए एक वर्ष में इतना ही दिया है जो एक वर्ष में इसके शेयरहोल्डर को दिए जाने वाले डिवीडेंट के 1.5 प्रतिशत के बराबर है। किसानों को इन पद्वतियों का खर्च तो स्वयं ही करना होगा, जबकि बड़ी कंपनियां इनका उपयोग अपने उत्सर्जन को जारी रखने के लिए करेंगी।

कृषि बिजनेस की कंपनियां रीजेनरेटिव खेती का उपयोग वित्तीय निवेशकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भी कर रही हैं। जो वित्तीय कंपनियां बहुत सी कृषि भूमि खरीद रही हैं, वे विज्ञापन देती हैं कि उनके यह औद्योगिक खेती के फार्म (संकीर्ण अर्थ में) 'रीजनरेटिव' भी होंगे, व इस तरह वे पेंशन फंड से धन व निवेश अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करती हैं। ब्राजील की सोयाबीन की खेती वाली कंपनी एस.एल.सी. एग्रीकोला (SLC Agricola) बहुत बड़े पैमाने के वन–विनाश के लिए जिम्मेदार है, पर इसने वित्तीय बाजार में हाल ही में 950 लाख डालर प्राप्त किए – रीजनरेट कृषि के नाम पर ईंधन की कुछ बचत वाले ट्रैक्टर, 'हरित खाद' व विभिन्न डिजीटल तकनीकों की खरीद के लिए।

रीजेनरेटिव खेती शब्द को कंपनियां द्वारा इतनी अच्छी तरह से अपना लिया किया गया है कि खाद्य संप्रभुता और 'एग्रो इकालाजी' या पर्यावरण रक्षा से सही अर्थों में जुड़ी कृषि, के लिए हमें इस शब्दावली के उपयोग से बचना चाहिए।

इस विषय की अधिक जानकारी के लिए इसे पढ़े (अंग्रेजी में):

- GRAIN, 2021, Agribusiness and big finance's dirty alliance is anything but "green" https://grain.org/e/6720
- IATP, 2021, Emissions impossible Europe: How Europe's big meat and dairy are heating up the planet https://www.politico.eu/wp-content/uploads/2021/12/12/Emissions-Impossible-IATP-report.pdf

कार्बन खेती (Carbon Farming)

औद्योगिक कृषि में रसायनों के अधिक उपयोग ने मिट्टी के आर्गेनिक या जैविक तत्त्वों को बड़े पैमाने पर नष्ट कर दिया है, व इस तरह दसियों लाख टनों के कार्बन का वायुमंडल में निकास कर दिया गया है। अब जब कार्बन क्षतिपूर्ति या ऑफसेट का बाजार बढ़ रहा है, जिन कंपनियों ने वर्षों या दशकों तक यह विनाश दिया है, वे अब तथाकथित 'कार्बन खेती' का प्रचार कर रही हैं कि वे इससे मिट्टी में फिर से इस कार्बन का निर्माण करेंगी।

किसानों को कार्बन खेती याजनों के लिए आनलाईन जोड़ा जाता है व उनसे विशेष कवर फसलें उगाकर व जुताई की जगह खरपतवार नाषक रसायनों का छिड़काव कर कार्बन को मिट्टी में स्थापित किया जा सके। कुछ वर्षों के बाद किसानों को इस आधार पर कुछ भुगतान किया जाता है कि मिट्टी में कितना कार्बन जमा हो सका। जिन देशों में बड़े पैमाने की औद्योगिक खेती होती हैं (जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, आस्ट्रेलिया व फ्रांस) वहां बड़ी कृषि कंपनियां जैसे बेयर (Bayer), यारा (Yara), कारगिल (Cargill) ने कार्बन फार्मिंग आरंभ की है या ऐसे प्रयासों से वे जुड़ी हुई हैं। वे इसके माध्यम से कार्बन क्रेडिट बेच कर उससे अपना हिस्सा कमाती भी हैं तथा साथ में इन कार्यक्रमों का उपयोग इस तरह करती हैं कि उनके डिजिटल कार्यक्रम में अधिक किसान जुड़ जाएं ये कंपनियां इनहें अपने उत्पाद जैसे बीज, कीटनाशक व खाद बेच सकें।

इन कार्बन कार्यक्रमों में अनेक कमियां हैं। इनका उपयोग ऐसे आफसेट या क्षतिपूर्ति सृजन के लिए होता है जिसका उपयोग कर अनेक बड़ी कंपनियों को अपने जीएचजी उत्सर्जन कम न करने का अवसर मिल जाता है। पर इस मुख्य विसंगति को

रहने दें तो भी किसी आफसेट कार्यक्रम में कम से कम कार्बन को वायुमंडल से स्थाई रूप से हटाने की गारंटी तो होनी ही चाहिए। कार्बन फार्मिंग कार्यक्रमों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि वे कार्बन मिट्टी को 10 वर्ष से अधिक रख सकें जबकि जलवायु बदलाव का संकट कम करने के लिए असर तब होगा जब इसकी कम से कम 100 वर्षों तक की व्यवस्था हो सके। यह गारंटी भी देना जरूरी है कि इस तरह कार्बन को मिट्टी में रखने की जो व्यवस्था हो रही है वह एक अतिरिक्त लाभ है, यह उसके अतिरिक्त है जो किसानों के कार्बन को मिट्टी में रखने के सामान्य प्रयास होते हैं। ऐसे प्रयास तो सामान्यतः किसान करते ही रहते हैं तथा आफसेट के चक्कर में पड़े बिना ही उन्हें यह कार्य और अधिक करने के लिए कई तरह से प्रोत्साहित किया जा सकता है जैसे जैविक खेती। एक अन्य समस्या यह ठीक–ठीक अनुमान लगाने की भी है कि कार्बन फार्मिंग से कितनी कार्बन मिट्टी में जमा हुई या इसी दौरान अन्य कारणों से खेती में कितना जीएचजी उत्सर्जन हुआ।

इतना जरूर कहना चाहिए कि किसानों को मिट्टी में कार्बन लौटाने के प्रयासों के लिए सहायता व प्रोत्साहन देना उचित है पर जिस तरह की कार्बन फार्मिंग का प्रसार इस के नाम पर हो रहा है, वह अनुचित है।

इस विषय की अधिक जानकारी के लिए इसे पढ़े (अंग्रेजी में):

- ECVC, 2022, Carbon farming: a "new business model"… for who? https://www.eurovia.org/wp-content/uploads/2022/03/ECVC-Carbon-farming-ENG.pdf
- GRAIN, 2022, From land grab to soil grab - the new business of carbon farming https://grain.org/e/6804
- IATP, NFCC, 2020, Why carbon markets won't work for agriculture https://nffc.net/iatp-and-nffc-report-on-carbon-markets-and-climate-policy/

जैव–अर्थव्यवस्था (Bioeconomy)

बायोइकानोमी (जैव अर्थव्यवस्था) पौधों व अन्य जैविक संसाधनों का उपयोग कर मैटीरियल, रसायन व ऊर्जा बनाती है। उदाहरण के लिए दवा कंपनियों द्वारा बनाई गए जैव विविधता आधारित औषधियां व प्रसाधन, फैट्रियां जो लकड़ी के चिप्स को जलाकर बिजली बनाती हैं, बसें जो गन्ने से प्राप्त एथेनोल से चलती हैं या मक्के के माड़ी (स्टार्च) से बनी प्लास्टिक की बोतलें। विभिन्न कंपनियां इस समय भी एक चौथाई बायोमास का उपयोग कर रही हैं व इसका पर्यावरण पर बहुत प्रतिकूल असर पड़ रहा है, पर अध्ययन बताते हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी 60 प्रतिशत इनपुट जैविक स्तर पर प्राप्त किए जा सकते हैं। **समर्थकों का तर्क है कि जैव. अर्थव्यवस्था जलवायु के लिए बेहतर है क्योंकि यह नवीकरणीय संसाधनों पर आधारित है।**

वैसे अधिकांश ग्राम समुदाय भी जैव अर्थव्यवस्था आधारित ही हैं। जहां बड़ी कंपनियां पॉम के पेड़ में पॉम तेल व पशु खाद्य के लिए ही रुचि रखती हैं, वहां पश्चिम व केन्द्रीय अफ्रीका (जहां पॉम पेड़ उत्पत्ती हुइ है) के ग्रामीण समुदाय सदा से पॉम के पेड़ के हर भाग से अनेक विविधता भरे खाद्य व अन्य उत्पाद प्राप्त करते हैं। पर कृषि बिजनेस कंपनियों की जैव अर्थव्यवस्था संबंधी अपनी एक विशिष्ट समझ है। वे इसे एक माध्यम समझते हैं जिससे वे अपने अनेक उत्पादों की बिक्री और बाजार बहुत बढ़ा सकें व इसके लिए वे पेटेंट की हुई तकनीकों जैसे कृत्रिम बायोलाजी (Synthetic Biology), नैनो टैक्नोलोजी व जीन एडिटिंग का उपयोग करते हैं। पॉम तेल कंपनियां ऊर्जा कंपनियों के साथ मिलकर पॉम तेल से हवाई जहाज का ईंधन बनाने के प्रयास कर रही हैं व इसके लिए ब्राजील व दक्षिण–पूर्व एशिया में पॉम तेल प्लांटेशन और बढ़ाने–फैलाने का कार्य चल रहा है।

बायोइकोनोमी की छतरी तले, जैव ईंधन (Biofuels) के इस्तेमाल को बढ़ावा देने का भी प्रयास हो रहा हैं। एक दशक पहले जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में व 'हरित ऊर्जा' के स्रोत के रूप में, जीससे जलवायु बदलाव से जझा जा सके जैव ईंधन का प्रचार–प्रसार अधिक हुआ था। मगर बायो डीजल व एथेनोल प्राप्त करने के लिए बढ़ते हुए मोनोकल्चर की वजह से शीघ्र ही यह चिंता उत्पन्न हुई कि ईंधन के लिए जमीन अधिक लिए जाने से खाद्य उत्पादन के लिए भूमि कम हो जा रही है। इसके अतिरिक्त बायोडीजल प्राप्त करने व जैव ईंधन के लिए जो तौर–तरीके उपयोग में लाए जा रहे थे उनमें भी जीएचजी उत्सर्जन अधिक हो रहा था व इसे शाश्वत ऊर्जा का उदाहरण नहीं माना जा सकता था।

बायोमास व जैव विविधता को धनी देशों के लिए एक उत्पाद बना कर कृषि बिजनेस की कंपनियां विकासशील व निर्धन देशों की भूमि व जैव विविधता का दुरुपयोग कर रही हैं व भूमि की छीनाछपटी व पर्यावरणीय क्षति को बढ़ावा दे रही हैं जबकि यह सब बायोइकोनोमी या जैव अर्थव्यवस्था के नाम पर किया जा रहा है।

इस विषय की अधिक जानकारी के लिए इसे पढ़े (अंग्रेजी में):

- BMBF Junior Research Group, 2020, Bioeconomy and Global Inequalities Socio-Ecological Perspectives on Biomass Sourcing and Production. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-030-68944-5.pdf
- ETC Group, 2014, Beware bioeconomy https://www.wrm.org.uy/bulletin-articles/beware-the-bioeconomy and Video animation on synthetic biology https://www.etcgroup.org/content/video-animation-synthetic-biology-5-languages
- Genetic Literacy Project, Global gene editing Regulation Tracker https://crispr-gene-editing-regs-tracker.geneticliteracyproject.org/
- HEÑÓI, Stay Grounded, Biofuelwatch & Global Forest Coalition, 2022, Biofuels case study: Omega Green https://stay-grounded.org/wp-content/uploads/2022/03/EN_agrofuels_case-study_2022.pdf

हरित वित्त (Green Finance)

'हरित वित्त' इस शब्दावली का उपयोग उन निवेश फंड व बांड (bonds) जैसे वित्तीय उपकरणों के लिए किया जाता है जो सामाजिक व पर्यावरणीय मानदंड आधारित होते हैं। यह मानदंड, जिन्हें पर्यावरणीय, सामाजिक व सुशासन (ई.एस.जी.) कहा जाता है, स्वैच्छिक हैं व उन्हें वित्तीय कंपनियों द्वारा ही निर्धारित व नियोजित किया जाता है। हालांकि 'हरित वित्त' का बाजार अभी छोटा व सीमित ही है – (यह कुल 118 खरब (ट्रिलियन) डालर की कुल वैश्विक पूंजी में से मात्र 1.7 खरब डालर वर्ष 2020 में था यानि 2 प्रतिशत से भी कम) पर इसमें तेज वृद्धि हो रही है। विश्व बैंक का अनुमान है कि इमरजिंग या तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं (देशों) में 'हरित बाण्ड' का बाजार अगले तीन वर्षों में 100 अरब डालर का हो जाएगा जबकि वर्ष 2030 तक 10 खरब डालर का हो जाएगा।

वित्तीय कंपनियां 'हरित वित्त' का उपयोग ऐसे अधिक व्यापक प्रयासों के एक हिस्से के रूप में कर रही हैं जिससे जलवायु बदलाव व अन्य पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के रूप में जो विभिन्न परियोजनाओं में सार्वजनिक निवेश होता है उस पर उनका नियंत्रण हो जाए। हरित वित्त के माध्यम से वित्तीय कंपनियां अपनी रुचि अधिक मुनाफा अर्जित करने व बड़े निर्णय लेने में रखती हैं, जबकि अधिकांश खर्च व जोखिम सरकारों (यानि लोगों) पर डाल दिया जाता है।

हरित बैंक कर्जे व पूंजी बाजार कर्जों को किसी टिकाऊ प्रोजेक्ट या पर्यावरणीय–सामाजिक परियोजना की शर्तों से जोड़ दिया जाता है। खाद्य व्यवस्था के संदर्भ में 'हरित वित्त' को बड़े पैमाने पर विशेष कृषि वस्तुओं के उत्पादन व 'प्रकृति आधारित समाधान' (nature based solutions) (एनबीएस) से जोड़ दिया जाता है।

जब नियंत्रण ब्लैक राक (BlackRock) जैसे बड़ी वित्तीय कपंनियों के हाथ में हो तो कोई आश्चर्य नहीं कि कृषि में आने वाला अधिकांश 'हरित वित्त' बड़ी कृषि बिजनेस कंपनियों के पास बड़े पैमाने पर विशेष कृषि वस्तुओं के उत्पादन के लिए ही उपयोग में आता है (हालांकि उस पर 'रीजेनरेटिव' 'क्लाईमेट स्मार्ट' व 'शून्य वन विनाश' का ठप्पा किसी न किसी तरह लगा दिया जाता है)। 'हरित वित्त' के माध्यम से वाल स्ट्रीट (Wall Street) प्रकृति का दुरुपयोग इस तरह करना चाहती है जिससे खाद्य, भूमि व प्राकृतिक संसाधनों व उससे जुड़ी कंपनियों पर उसका या वित्तीय पूंजी का नियंत्रण और बढ़ सके। इस खतरनाक प्रवृत्ति को रोकने के लिए जरूरी है कि वित्त व निवेश को सार्वजनिक व सामुदायिक नियंत्रण में रखा जाए व बड़ी वित्तीय कंपनियों व कृषि बिजनेस कंपनियों से मुक्त रखा जाए।

इस विषय की अधिक जानकारी के लिए इसे पढ़े (अंग्रेजी में):

- Daniela Gabor, The Guardian, 4 June 2021, “Private finance won’t decarbonise our economies – but the ‘big green state’ can” https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/jun/04/private-finance-decarbonise-economies-green-state
- GRAIN, 2021, Agribusiness and big finance's dirty alliance is anything but "green" https://grain.org/e/6720
- Grupo Carta de Belém, 2022, Brasil na Retomada Verde: integrar para entregar (पुर्तगाली में)

ग्रेन के इंस्टाग्राम और फेसबुक में ग्रीनवॉशिंग टूलकिट इन्फोग्राफिक देखें !

● ● ●

ग्रेन (GRAIN) एक अंतरराष्ट्रीय अलाभकारी संगठन है जो छोटे किसानों और सामाजिक आंदोलनों को जैव विविधता आधारित और समुदाय नियंत्रित भोजन व्यवस्था के लिए उनके संघर्षों में सहयोग करता है। ग्रेन प्रत्येक वर्ष बहुत सी रिपोर्ट निकालता है जो दिए हुए विषयों पर गहरे स्रोत के दस्तावेज होते हैं और प्रामाणिक पृष्टभूमि के साथ विषय का विश्लेषण उपलब्ध कराते हैं।

ग्रेन की रिपोर्टों का पूरा संकलन हमारी इस वेबसाइट पर प्राप्त किया जा सकता है।
http://www.grain.org